भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2053

22 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

आवास विहीन और बीपीएल जनसंख्या

2053. **श्री रवि किशनः**

श्री मनोज तिवारीः

श्री जॉन बर्लाः

श्री संगम लाल गुप्ताः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बीपीएल श्रेणी से संबंधित गरीब आवासविहीन लोगों का कोई सर्वेक्षण करवाया है(

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है(

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त वर्णित निराश्रित लोगों को स्थायी घर प्रदान करने का है(और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): जी हां। दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय की स्कीम (एसयूएच) के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में स्थानीय/नगर निकायों द्वारा एक सुव्यवस्थित तृतीय पक्ष सर्वेक्षण किए जाने का प्रावधान है जिससे कि उपयुक्त स्थानों पर आश्रयों की आवश्यकता का सटीक आकलन किया जा सके । अब तक, 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने तृतीय पक्ष सर्वेक्षण किया है जिसके द्वारा 207, 847 शहरी बेघर व्यक्तियों की पहचान की गई है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं । अत: यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का दायित्व है कि वे बेसहारा लोगों को स्थायी आवास मुहैया कराने के लिए नीतियां बनाएं और स्कीमों का कार्यान्वयन करें । तथापि, भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास

योजना -शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि बेसहारा व्यक्तियों सहित पात्र शहरी गरीबों को बुनियादी नागरिक सुख-सुविधाएं प्रदान की जा सके ।

****

अनुलग्नक

दिनांक 22.09.2020 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2053 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तृतीय पक्ष सुव्यवस्थित सर्वेक्षण में पहचान किए गए शहरी बेघरों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहचान किए गए शहरी बेघर व्यक्तियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	11,173
2	बिहार	10,253
3	चंडीगढ़	2,064
4	छत्तीसगढ़	10,216
5	गोवा	173
6	गुजरात	35,293
7	हरियाणा	19,015
8	हिमाचल प्रदेश	879
9	झारखंड	1,735
10	केरल	3,195
11	मणिपुर	4
12	मेघालय	48
13	मिजोरम	3,888
14	नागालैंड	50
15	ओडिशा	13,651
16	पुडुचेरी	719
17	राजस्थान	39,512
18	सिक्किम	13
19	तमिलनाडु	14,040
20	तेलंगाना	2,952
21	उत्तर प्रदेश	28,409
22	पश्चिम बंगाल	10,565
कुल		**207847**